- (d) The work on the project is being done by the Government of Bihar both departmentally and through contractors.
- (e) and (f). The proposed Kosi Control Board has not yet been constituted, as concurrence of the Government of Bihar to setting up of this Board is yet awaited.

गंग नहर में पानी छोड़ा जाना

190. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या रिसचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) गत तीन वर्षों से राजस्थान में गंग नहर में कितने क्यूसेंक पानी छोड़ा जा रहा है;
- (ख) क्या मरम्मत न होने के कारण ग्रथवा नहर में गाद जमा हो जाने के कारण पूरा पानी नहीं छोड़ा गया ;
- (ग) यदि हां, तो सुधारात्मक उपाय न किये जाने के क्या कारण हैं; ग्रौर
- (घ) यदि ऐसे उपाय किये गये हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रास्य में राज्य मंत्री (त्री जियाउर्रहमान ग्रंसारी): (क) पंजाब में पड़ने वाले नहर के ऊपरी भाग को बीकानेर नहर कहा जाता है। पंजाब-राजस्थान सीमा के बाद इसे गंग नहर कहा जाता है। बीकानेर नहर के शीर्ष पर इस नहर में छोड़े जाने वाले जल की मान्ना ग्रीर पंजाब-राजस्थान सीमा पर राजस्थान को दिए जाने वाले जल की मान्ना, राजस्थान द्वारा दी गई सूचना के स्रनुसार, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ). यद्यपि कानेर नहर की लाइनिंग खराब हो गई है और इसकी मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है, लेकिन भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट संलग्न विवरण से पता चलता है कि बीकानेर नहर पिछले तीन वर्षों के दौरान 2720 क्यूसेक की अपनी ग्रिभिक्तिय क्षमता के अनुसार जल लाती रही है। तथापि, पंजाब-राजस्थान सीमा पर पहुंचने वाला जल 2640 क्यूसेक के ग्रिभिक्तिपत निस्सरण से कम है। यह शायद लाइनिंग के खराब होने के परिणामस्वरुप बहुत अधिक रिसन होने के कारण है।

बीकानेर नहर की लाइनिंग की मरम्मत करने के प्रकृत पर पंजाब स्रौर राजस्थान सरकारों के साथ विचार किया जा रहा है ताकि राजस्थान क्षेत्र में गंग नहर को सिचाई के जल की सप्लाई पर प्राप्त प्रभाव डाले विना उक्त कार्य को हाथ में लेने के लिए परस्पर-सम्मत करार किया जा सके । चूंकि दोनों राज्य सरकारें इस बारे में किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकीं, इसलिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई हैं जिसके परिणामस्वरुप दोनों राज्यों के मुख्य इंजीनियर अपने-अपने प्रस्तावों में निहित लागत-अनुमानों तथा ग्रन्थ बातों की पुनः जांच कर रहे हैं। इस जांच और ग्रध्ययनों के परिणाम ग्रभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

	बीकाने	बीकानेर शहर में जल का डिस्चार्ज शीर्ष पर					(मासिक श्रौसत क्यूसेकों में) पंजाब-राजस्थान सीमा पर				
	1977-	1978- 79	1979- 80	1980- 81	1977- 78	1978- 79	1979-	1980- 81			
	78										
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
म प्रैल	. 2614	2720	1817	2713	2289	2383	1594*	2172			
मई" 🕆	. 2211	2504	2684	2222	1903	2174	2322	1834			

1		2	3	4	5	6	7	8	9
जून .	•	2105	2720	2720	2318	1780	2401	2308	1997
जुलाई		2720	2294	2720	2381	2361	2068	2365	1968
ग्रगस्त		2720	2097	2172	2466	2412	1872	1812	2066
सितम्बर		2720	2588	2624	2027	2440	2257	2269	1687
ग्रक्तूबर		2720	2720	2631	2002	2372	2374	2283	1604
नवम्बर	•	2720	2720	2194	1897	2312	2356	1846	1739
दिसम्बर	•	2720	2720	2365	(26-11- 1980)	2312	2356	1997	(20-11
जनवरी		2720	2711	1995	तक	2326	2288	1694	तक
फरवरी		2720	2713	2252		2357	2255	1900	
मार्च		2661	2720	2585		2292	2358	2268	

नहर को 10-4-79 से 16-4-79 तक बंद रखा गया था

Commemorative Stamp on Hijri Calendar

*191. SHRI G. M. BANATWALLA: SHRI RAM AWADH:

Will the Minister of COMMUNI CATIONS be pleased to state:

- (a) whether the commemorative stamp on the occasion of 1400th Anniversary of the Muslim Hijri calendar was released prematurely;
- (b) if so, the details of the circumstances leading to premature release; and
- (c) the details of enquiry, if any, and the action taken thereon by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Enquiry is in progress. Further action would be taken after the receipt of the Enquiry Report.

Bill re. Job Quotas for Disabled

- *192. SHRI N. E. HORO: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
- (a) whether Government propose to bring up a comprehensive Bill laying down job quotas for the disabled; and
 - (b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): (a) and (b). The Government have set up a Working Group to consider the advisability of taking legislative measures for economic rehabilitation and social integration of handicapped persons. Report of the Group is awaited.